ACHIEVER IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

HINDI

27/06/2023

TALK TO US

+918434931877, +917250667974

achieveriaspatna@gmail.com

www.achieveriaspatna.co.in

NEW PATLIPUTRA COLONY ROAD NO. 4A, NEAR TENNIS COURT, PATNA-13

द हिंदू 07-06-2023

राष्ट्रीय

⇨ केंद्र कुकिस के साथ समझौते का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा : बीरेन.

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि एचएम अमित साह ने वादा किया है कि केंद्र पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी विद्रोही समूह के साथ निलंबन समझौते (500) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

500 - कुकी विद्रोही समूह और सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए। 2008 में भारत के कुकी विद्रोही समूह ने हथियार छोड़ने और एक अलग कुकी राज्य की अपनी मांग छोड़ने पर सहमति व्यक्त की।

हालाँकि, हाल ही में मणिपुर हिंसा के दौरान कई विद्रोहियों के खिलाफ अपने हथियार चलाने की संभावना है, सीएम ने कहा कि 10 जिलों में से केवल 3 - कांग कोपकी, टेंग नौपाल और चुरूराचादपुर में हाल के समय में हिंसा देखी गई है।

19 पुलिस स्टेशनों से सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (एएफएसपीए) को हटाना सशस्त्र बलों के लिए कम समय में काम करना एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है और उन्हें कई चीजों के लिए नागरिक सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।

⇨ उच्च पीएफ पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि जुलाई तक बढ़ाई गई"

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई में उच्च पीएफ पेंशन भरने के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

⇨ मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी संघ पीड़ित पक्ष के साथ नहीं है।

ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन (एएमटीयू) ने मणिपुर एचसी के 27 मार्च के आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें राज्य सरकार को भारत सरकार के इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा गया था कि क्या मैतेई को एसटी में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं।

26 जून को मणिपुर HC में मामले की सुनवाई हुई.

मणिपुर सरकार ने अदालत में कहा कि एएमटीयू एक पीड़ित पक्ष नहीं है और उसके पास 27 मार्च के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

मैतेई समूह वर्षों से एसटी राज्यों की मांग कर रहा था, इसलिए यह मामला मैतेई समूह और संसद के बीच है, जिसके पास किसी समूह को एसटी सूची में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति है।

एएमटीयू पूरी तरह से तीसरी पार्टी है। ये है मणिपुर सरकार का मांस.

⇨ पहले कांग्रेस अध्यक्ष बीरेन सिंह को बर्खास्त करें, प्रधानमंत्री से आग्रह।

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खेरगे ने सोमवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे पहले मणिपुर के सीएम एन. बीरेन सिंह को बर्खास्त करना चाहिए, उन्होंने राज्य में हिंसा पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाया।

⇨ मोदी ने मणिपुर की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की

पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मणिपुर पर वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की, जिसमें ईंधन की उपलब्धता, कर्मचारियों की सहमति और मणिपुर के लिए वित्तीय पैकेज पर चर्चा होने की उम्मीद है।

⇨ पैदल चल रही महिला कार्यकर्ता मणिपुर में मार्गों को अवरुद्ध कर रही हैं'

सेना ने सोमवार को कहा कि मणिपुर में महिला कार्यकर्ता सशस्त्र दंगाइयों के साथ थीं और जानबूझकर मार्गों को अवरुद्ध कर रही थीं और सुरक्षा बलों के अभियान में हस्तक्षेप कर रही थीं।
सेना द्वारा चिपकाए गए एक वीडियो में महिलाओं को सड़कों को अवरुद्ध करते हुए और सशस्त्र विद्रोहियों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग करते हुए दिखाया गया है।
'मणिपुर में महिलाओं के नेतृत्व में शांतिपूर्ण नाकाबंदी के मिथक को ध्वस्त' शीर्षक वाला वीडियो तीन घटनाओं का वर्णन करता है जहां महिलाएं सड़कों को अवरुद्ध करती हुई और दंगाइयों का समर्थन करती हुई दिखाई देती हैं।

⇨ विपक्षी नेताओं का कहना है कि असम में मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र कम होंगे।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीपी) ने कहा है कि मसौदा प्रस्ताव मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों को पहले के 29 से बढ़ाकर 22 तक सीमित कर देता है।

⇨ ईसीआई द्वारा परिसीमन का मसौदा।

विधान सभा

ACHIEVERS IAS ACADEMY

	New division	Old division
General	98	102
SC	9	8
ST	19	
Total	126 Seats	

परिसीमन प्रस्ताव के मसौदे में कुल लोकसभा सीटें (14) या कुल विधानसभा सीटें (126) पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

- एसटी विधानसभा सीटों की संख्या 16 से बढ़कर 19 हो गई है.
- एससी सीटें 8 से बढ़कर 9 हो गईं.

⇨ एसजीपीसी ने पंजाब सरकार से कहा, सिख गुरुद्वारा बिल वापस लें अन्यथा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।

⇨ श्रीमोनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने सोमवार को अमृतसर में आयोजित एक विशेष सत्र में सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में पंजाब सरकार के हस्तक्षेप की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

एसजीपीसी - यह गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्रमुख सिख निकाय है।

गुरुबानी ब्रॉडकास्ट अधिकार एसजीपीसी द्वारा दिए गए हैं और वर्तमान में जी-नेक्स्ट मीडिया (पीटीसी चैनल) के पास हैं, जिसका स्वामित्व सुखबीर सिंह बादल (श्रीमोनी अकाली दल प्रमुख) के पास है।

पंजाब विधानसभा ने हाल ही में सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया, इसने स्वर्ण मंदिर से गुरबानी (पवित्र भजन) के प्रसारण के अधिकार को मुक्त कर दिया।

एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धाम ने बताया कि कोई भी संशोधन करने से पहले एसजीपीसी सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की मंजूरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार "सिख विरोधी विचारधारा" के साथ काम कर रही है।

सीएम भागवत ने एसजीपीसी अध्यक्ष पर एसएपी के "मुख्य प्रवक्ता" के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया।

⇨ **एनएमसी ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए नवीनतम नियम वापस लिया।**

⇨ **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए हाल ही में जारी स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 2023 को वापस ले लिया है।**

12 जून को, एनएमसी ने योग्यता आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम, मेडिकल कॉलेज में अनुसंधान सुविधाओं के लिए जनशक्ति की भर्ती, विकलांग श्रेणी के तहत छात्रों के लिए प्रवेश और प्रवेश जमा करने के प्रारूप पर नए नियमों के साथ दिशानिर्देश जारी किए थे।

इसने मेडिकल कॉलेजों को 30 अगस्त से पहले प्रवेश पूरा करने के लिए कहा था। इसके अलावा नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) हर साल दिसंबर और जनवरी में आयोजित किया जाना था।

नवीनतम एनएमसी परिपत्र में कहा गया है कि 12-06-2023 परिपत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

⇨ **अचानक आई बाढ़ के कारण भूस्खलन से हिमाचल के राजमार्ग बाधित हो गए, जिससे सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं**

अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया।

⇨ श्रमिकों पर अत्याचार पर एनएचआरसी ने महाराष्ट्र को भेजा नोटिस:-

⇨ **अप्रैल से अब तक 149 चार धाम यात्रियों की बीमारियों और दुर्घटनाओं से मौत हो गई।**

उत्तराखंड में चार धाम

यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ।

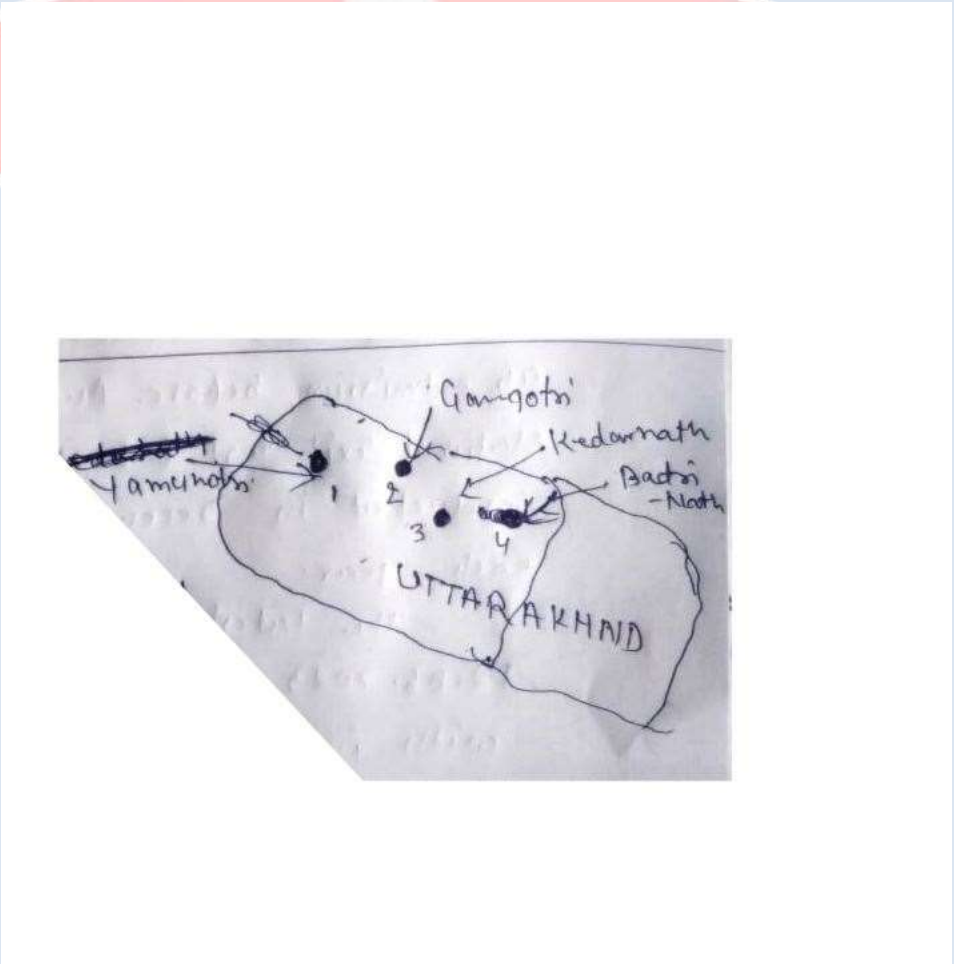

तीर्थयात्रा का मौसम 22 अप्रैल से शुरू हुआ और नवंबर तक चलेगा।
इस वर्ष अब तक 31.78 लाख लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं।
इसे 50 लाख पार करने का अनुमान है. पिछले साल, यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में 40 लाख तीर्थयात्री आए थे, पहले 65 दिनों के सीज़न में 149 लोगों की मौत हो गई थी। केदारनाथ में 72, यमुनोत्री में 28, बद्रीनाथ में 27 और गंगोत्री में 16।

दुनिया

⇨ म्यूट करने के बाद अनिश्चितता घूमते हुए प्रिगोझिन ने उद्दंड बयान जारी किया

जारी किए गए 11 मिनट के वीडियो में, एचआर प्रिगोझिम ने रूसी राज्य पर हमला करने की कोशिश से इनकार किया और कहा कि उन्होंने अपने बल पर हमले के जवाब में कार्रवाई की जिसमें उनके 30 लड़ाके मारे गए। श्री प्रिगोझिम ने बताया, "हमने अन्याय के कारण अपना मार्च शुरू किया।"
सोमवार को पुतिन ने ईरान और कतर के नेताओं से बातचीत की।

पुतिन का विश्वास खो देने की अटकलों के बीच सर्गेई शोइगु सैन्य प्रमुख भी चुप रहने के बाद पहली बार सामने आए। वैगनर की म्यूटिंग से पता चलता है कि यूक्रेन पर रूस की "रणनीतिक गलती" थी: नाटो प्रमुख।

नाटो प्रमुख जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने सोमवार को कहा कि रूस में भाड़े के सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह दिखाता है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण एक "गलती" थी।

⇨ चुनौतियों के बीच श्रीलंका अपने घरेलू ऋण का पुनर्गठन करेगा :-

श्रीलंका अपने घरेलू ऋण के पुनर्गठन की सरकार की योजना पर संसद में एक असाधारण सप्ताहांत बहस से पहले, गुरुवार से शुरू होने वाले पांच दिनों के लिए अपने बैंकों और वित्तीय क्षेत्र को बंद कर देगा।

आईएमएफ ने श्रीलंका को 3 अरब का बेलआउट पैकेज दिया था.

श्रीलंका पर 41 अरब का कर्ज है.

ऋण के पुनर्गठन का मतलब परिपक्वता अवधि का विस्तार हो सकता है। एक बाल कटवाना. घरेलू ऋणदाताओं द्वारा कटौती किए जाने से बुजुर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है

वैगनर न्यूटिनी को समझना

रूस को अभूतपूर्व आंतरिक सुरक्षा संकट में डालने का कारण क्या था? वैगनर निजी सैन्य कंपनी का प्रमुख इसमें क्यों शामिल है?

पुति ने इससे कैसे निपटा?

क्या इसने पुतिन के कमजोर होते अधिकार को दर्शाया है?

अब तक कहानी :-

रूस की वैगनर निजी सैन्य कंपनी के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन ने 24 जून को देश की रक्षा प्रतिष्ठान के खिलाफ एक अल्पकालिक मौन रखा।

प्रिगोझिन की मांग थी कि रक्षा प्रमुख सर्गेई शोइगु को हटाया जाए। इससे गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। श्री प्रिगोझिम ने विद्रोह का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने कई अनसुलझे मुद्दे छोड़ दिए जो क्रेमलिन को परेशान कर सकते हैं।

वैगनर न्यूटिनी

⇨ 24 जून को क्या हुआ था?

23 जून की रात को श्री प्रिगोझिन ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रक्षा नेतृत्व पर वैगनर पर हमले का आदेश देने और उसके कई बलों को मारने का आरोप लगाया गया।

कुछ घंटों बाद, उन्होंने एक और वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि उनकी सेना ने रूस के दक्षिणी सैन्य जिला मुख्यालय रुसियोव-ऑन-डॉन पर कब्जा कर लिया है।

श्री प्रिगोज़्म ने कहा कि वैगनर न्याय के लिए मास्को की ओर एक मार्च शुरू करेंगे।

काफिला रोस्टन को मॉस्को से जोड़ने वाले मुख्य राजमार्ग की ओर बढ़ने लगा, वैगनर बलों ने डॉन पर छह रूसी हेलीकॉप्टर और एक कमांड सेंटर विमान को गोली मार दी, जिसमें 13 सैनिक मारे गए। जब रूसी सैनिकों ने वैगनर को रोकने की कोशिश की तो सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए। शनिवार की रात को।

यह 21वीं सदी की सबसे खूनी लड़ाई में से एक थी।

हालांकि वैगनर ने लगभग 20,000 लोगों के साथ बखमुट पर कब्ज़ा कर लिया।

प्रिगोझिन ने कहा, "जितना सोचा गया था उससे पांच गुना अधिक लोग मारे गए" उन्होंने जवानों की इस हानि के लिए रक्षा मंत्रालय नेतृत्व पर आरोप लगाया। बाद में श्री प्रिगोझिन ने कहा कि बख्रुत से पीछे हटते समय उनके लोग गोलीबारी की चपेट में आ गए।

10 जून :- रक्षा मंत्री ने एक आदेश जारी कर सभी सशस्त्र स्वयंसेवकों को 1 जुलाई से पहले रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। श्री प्रिगोझिन ने वहां की घटनाओं का विरोध किया जिसके कारण 24 जून को म्यूट कर दिया गया।

⇨ पुतिरिस की प्रतिक्रिया क्या थी

एक टीवी में, रूसी राष्ट्रपति के संबोधन में, मास्को से लगभग 200 किमी दूर सशस्त्र म्यूटिंग को "विश्वासघात" कहा गया, श्री प्रिगोझिम ने बेलारूस से ठीक पहले "यह खत्म हो गया" बताते हुए एक और वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री लुकाशेंको ने घोषणा की कि युद्धविराम पर सहमति बन गई है।

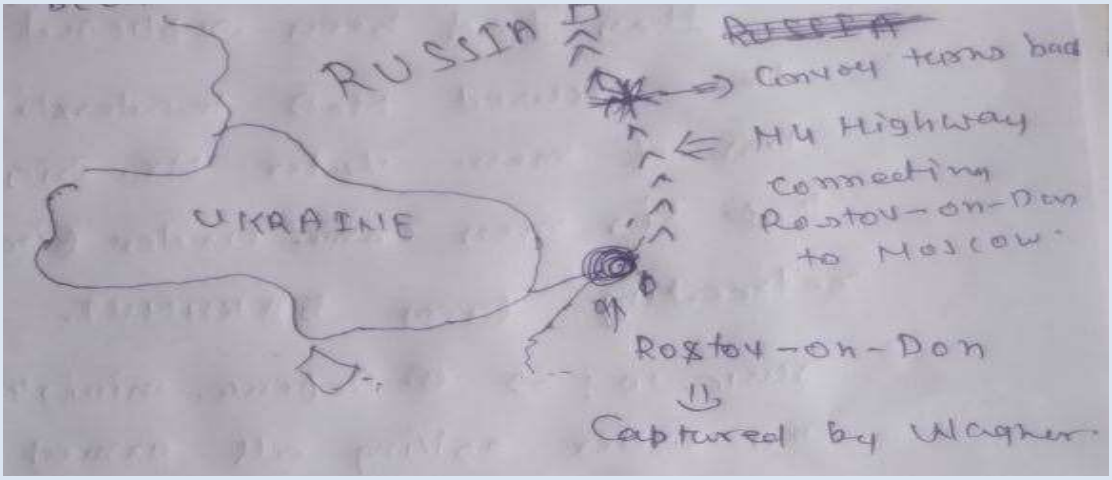

⇨ प्रिगोझिन ने विद्रोह क्यों शुरू किया?

रूस के रक्षा मंत्रालय और प्रिगोझिन के बीच उनका मतभेद पहली बार फरवरी में सामने आया जब उन्होंने मंत्रालय पर वैगनर को केवल सीमित हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने का आरोप लगाया।

बखमुत की लड़ाई

और एक "पीछे कदम" बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सुरक्षा सेवाओं को विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया है।

लेकिन लगता है पुतिन अभी भी दुविधा में थे.

वैगनर रूस के लिए बहुत प्रभावी साबित हुआ है इसलिए राष्ट्रपति ने खूनी गृहयुद्ध के बजाय चेहरा बचाने का रास्ता चुना।
उन्होंने बेलोरूसिया लुकाशेंको की ओर रुख किया जिन्होंने प्रिगोझिम के साथ बातचीत की और एक समझौता हुआ।
सौदा क्या था?
एक बार जब प्रिगोझिन ने चुप रहना शुरू कर दिया तो उस पर आपराधिक आरोप लगा दिए गए। इन आरोपों को छोड़ना पड़ा, प्रिगोझिन को बेलारस वैगनर बलों में निर्वासित किया जाएगा, जिन्होंने म्यूटिंग में भाग नहीं लिया था, उन्हें रक्षा मंत्रालय के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई थी।
आगे क्या होगा
म्यूटिंग ने श्री पुतिन के कमजोर होते अधिकार को उजागर कर दिया है, ऐसी स्थिति भविष्य में भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि कुछ ही लोग प्रिगोझिन द्वारा अपनी खुद की शुरुआत करने की म्यूटिंग को देख सकते हैं।
रूस का युद्ध क्षेत्र में ख़राब प्रदर्शन, आंतरिक कलह, भ्रष्टाचार के आरोप अनसुलझे रहे।
यदि युद्ध बिना किसी ठोस नतीजे के और लंबा खिंचता है तो श्री प्रिगोझिम को इससे और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है

शोलेदार और बखमुत - 2023 में रूस द्वारा कब्जा किए गए दो मुख्य शहर।
वैगनर ने वहां दोनों को पकड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई।

सम्पादकीय-1

एक भव्य पुनरुद्धार

- **भारत और मिस्र ने हाल के वर्षों में घनिष्ठ संबंध फिर से स्थापित किए हैं।**
- **संपादकीय किस बारे में है?**

संपादकीय पीएम मोदी की मिस्र यात्रा के बारे में है, जो बेहद सफल रही थी।

⇨ पीएम की यात्रा और हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में?

प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय और समझौते पर हस्ताक्षर

- मिस्र और भारत अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत करने पर सहमत हुए।
- दोनों देश हरित ऊर्जा, फार्मा क्यूटिकल्स और रक्षा में घनिष्ठ सहयोग पर सहमत हुए
- कृषि, पुरातत्व और पुरावशेषों और प्रतिस्पर्धा कानून पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

मुस्लिम जगत के प्रति अपनी सरकार की नीतियों के बारे में गलतफहमियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की।

पीएम को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान "द ऑर्डर ऑफ द माइल" से सम्मानित किया गया

सितंबर में दिल्ली में होने वाले जी-20 में मिस्र को विशेष आमंत्रित किया गया है।

⇨ भारत और मिस्र के ऐतिहासिक संबंधों के बारे में

- 1956 में स्वेजलैंड संकट के दौरान भारत ने मिस्र का समर्थन किया
- मिस्र और भारत दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के संस्थापक सदस्य थे।
- रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों देशों में समान बंटवारा है।
  रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति प्रभावित होने के बाद पिछले साल भारत ने मिस्र को रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं की आपूर्ति की थी।